इकाई–6 नीति निरूपण एवं नियोजन

अध्याय–15
नीति आयोग
(Niti Aayog)

वर्तमान समय में नियोजन (Planning) का विशेष महत्व है। नियोजन को योजना भी कहते है। आज लगभग सभी देश अपने विकास तथा उन्नति के लिए नियोजन में जुटे हुए है। मूलतः यह साम्यवादी विचारधारा के आलोक में आरम्भ हुआ लेकिन शीघ्र ही इसने अपने अलग–अलग रूपों में विभिन्न देशों में लोकप्रियता प्राप्त कर ली। किसी अर्धविकसित देश के लिए, जहाँ सीमित संसाधनों द्वारा एवं निश्चित समय में विकास की गति प्राप्त करनी हो, नियोजन का विशेष महत्व है। नियोजन का अर्थ होता है, सही ढंग से सोच समझकर कार्य करना। यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है। सरल शब्दों में कह सकते है कि निर्धारित उद्धेश्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर सर्वोत्तम मार्ग का चयन करना ही नियोजन है। इसके अन्तर्गत् अनेक क्रियाएं शामिल है, यथा– उद्धेश्य का निश्चय करना, उद्धेश्य प्राप्ति हेतु प्रस्तावित रणनीति पर विचार करना तथा रणनीति का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना। हैनरी फेयोल के अनुसार नियोजन ''पूर्व दृष्टि है।'' पिफनर के मत में ''यह समस्त मानव व्यवहारों में पायी जाने वाली बुद्धिमतापूर्ण प्रक्रिया है।'' सेकलर–हडसन का मानना है कि ''नियोजन भावी कार्य के लिए आधार की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया है।''

नियोजन की आवश्यकता (Need of Planning)

विकासशील देशों में नियोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इन देशों में सरकार का यह दायित्व है कि वे उपलब्ध मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का उचित एवं उत्तम ढंग से प्रयोग करे। विकासशील देशों को कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे – कृषि पर निर्भरता एवं पिछड़ी हुई कृषि पद्धति, गरीबी, अशिक्षा, व्यापार में निवेश हेतु पूंजी की कमी, आधुनिक तकनीकी ज्ञान का अभाव, दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पर्यावरणीय कानूनों की अवहेलना, शासन–प्रशासन में व्याप्त अनियमितताएं आदि। इनसे राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी समस्याओं के रहते विकास करने हेतु नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। नियोजन के माध्यम से विकासशील देश अग्रलिखित परिवर्तन कर सकते है :

1. देश में आर्थिक स्थिरता लाना।
2. नागरिकों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक असमानता में कमी लाना।
3. प्रति व्यक्ति आय सहित राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
4. प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग करना।
5. संतुलित क्षेत्रीय विकास।

विकास प्रशासन विकासशील देशों का महत्वपूर्ण लक्षण है, विकास प्रशासन वह प्रशासन है जो विकास हेतु नीति, योजना, परियोजना में संलग्न है। अतः विकास प्रशासन सहित उपयुक्त घटकों की प्राप्ति हेतु नियोजन एक आधारभूत आवश्यकता है।

भारत में नियोजन (Planning in India)

भारत में नियोजन का नाम सर्वप्रथम वर्ष 1934 में सुनने में आया, जब एम.विश्वेश्वरैया ने देश की आय को दूगुना करने के उद्धेश्य से एक 10 वर्षीय योजना बनाई। लेकिन इस संबंध में व्यवस्थित शुरूआत योजना आयोग (Planning commission) की स्थापना के साथ हुई। भारत सरकार द्वारा 15 मार्च, 1950 को इसकी स्थापना की गई। केन्द्र स्तर पर स्थापित यह संस्था भारत में एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली परामर्शदात्री अभिकरण रहा है। परामर्शदात्री संस्थाएं वह अभिकरण होते है जिनका दायित्व निश्चित उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार को मात्र परामर्श देना होता है, उद्धेश्यों का वास्तविक क्रियान्वयन इनकी जिम्मेंदारी नहीं होती हैं। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों का प्रभावशाली एवं संतुलित उपयोग हो, इस हेतु योजना बनाना तथा समय–समय पर योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा नीति एवं उपायों में आवश्यक तालमेल हेतु सिफारिश करना था।

पूर्ववर्ती योजना आयोग (Planning Commision):

योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में की गई थी। इस प्रकार, योजना अयोग न ही संवैधानिक निकाय है और न ही विधायी। दूसरे शब्दों में , इस आयोग की स्थापना न तो संविधान के अधीन हुई है और न ही किसी अधिनियम के माध्यम से। भारत में, योजना आयोग सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु नियोजन के सर्वोच्च निकायों में से था।

कार्य और भूमिका (Function and Role)–दिनांक 15 मार्च, 1950 के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे –

1. देश की भौतिक, पूँजी और मानव संसाधनों का आंकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएँ तलाशना।
2. देश के संसाधनों की सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग में लाने संबंधी योजना बनाना।
3. योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना।
4. आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का उल्लेख करना।

5. प्रत्येक चरण में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा तथा आवश्यक समायोजनों की अनुशंसा करना।
7. आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित समूचित अनुशंसा करना।

योजना आयोग द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया है। पंचवर्षीय योजना से अभिप्राय उन पाँच वर्षीय योजनाओं से जिनके माध्यम से देश के बहुआयामी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण आगे दर्शाया गया है :

भारत में योजनाएँ :

भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। भारत में अभी तक 11 पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है, तथा वर्तमान में 12 वीं योजना चल रही है। इनका संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित है –

प्रथम योजना (1951–1956) – इस योजना में मुख्यतः बाँध, बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएँ, कृषि आदि क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। योजना के अंत में (1956) में पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) शुरू किए गए। यह एक सफल योजना थी।

दूसरी योजना (1956–1961) – दूसरे पाँच सालों में उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

तीसरी योजना (1961–1966) – इसमें कृषि क्षेत्र विशेषकर गेहूँ के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। इस योजना काल में देश में 5.6 प्रतिशत की विकास दर हासित करने का लक्ष्य था, लेकिन योजनाकाल में भारत–चीन एवं भारत–पाकिस्तान युद्ध होने से विकास दर निम्न रही। इस दौरान 2.84 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई।

चतुर्थ योजना (1969–1974) – हरित क्रान्ति पर जोर दिया गया। 14 प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) किया गया।

पंचम योजना (1974–1979) – इसका प्रमुख लक्ष्य रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं न्याय था। इसमें लक्ष्य 4.4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना था, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.8 प्रतिशत प्राप्त हुई।

छठी योजना (1980–1985) – इस योजना में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला। इसमें लक्ष्य 5.2 प्रतिशत विकास दर प्राप्ति का था लेकिन व्यवहार में 5.66 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई।

सप्तम योजना (1985–1989) – सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी उद्योगों) की उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया गया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया गया। इस योजना में लक्ष्य 5.0 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करना था जबकि वास्तविक प्राप्ति 6.01 प्रतिशत की हुई।

1989–1991 की वार्षिक योजनाएँ – इस दौरान देश में कतिपय आर्थिक कारणों से एक–एक साल की योजनाएँ प्रस्तुत की गई।

आठवीं योजना (1992–1997) – देश में मुक्त अर्थव्यवस्था की शुरूआत भारत में उदारीकरण–निजीकरण–वैश्वीकरण की नीति आरम्भ हुई।

नौवीं योजना (1997–2002) – इस योजना में तीव्र औद्योगीकरण, मानव विकास, पूर्ण रोजगार, गरीबी में कमी तथा घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य थे।

दसवीं योजना (2002–2007) – इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने हेतु अलग–अलग प्रतिशत लक्ष्य रखे गए। यह संकेतात्मक नियोजन (Indicative Planning) की स्पष्ट शुरूआत की थी। इस योजना का लक्ष्य समानता पर आधारित सतत् विकास था। इसमें 7.6 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई।

ग्यारहवीं योजना (2007–2012) – इस योजना का मुख्य लक्ष्य **समावेशी विकास** (Inclusive Growth) था। इससे अभिप्राय है कि देश के सभी क्षेत्रों एवं सभी लोगों का विकास हो। इस हेतु इस योजना में विभिन्न क्षेत्रों हेतु अलग–अलग लक्ष्य रखे गए।

बारहवीं योजना (2012–2017) – इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत का **तेज, अधिक समावेशी एवं सतत् विकास** (Faster,More Inclusive and Sustainable Growth) करना है। यह योजना वर्तमान में जारी है इस योजना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर 8 प्रतिशत विकास दर प्राप्ति का लक्ष्य है।

नई संस्था की आवश्यकता (Need of New Instutution) –

योजना आयोग की स्थापना के साथ से ही इसकी भूमिका तथा कार्यप्रणाली पर अलग–अलग ढंग से प्रश्न उठाये गये है। यद्यपि इसने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास में योगदान दिया तथापि इसे कभी सुपर केबिनेट (जो समस्त निर्णय स्वयं ही करे) तो कभी मंत्रिमण्डलीय तानाशाही का अभिकरण माना गया है। इसने भारतीय संघवाद की मूल आत्मा पर प्रहार कर विकेन्द्रीकरण की जगह शक्तियों के केन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया। जिस परंपरागत योजना आयोग ने भारत की संपूर्ण नियोजन प्रणाली (Planning System) का प्रतिनिधित्व किया, वह समय के साथ कई खामियों के चलते निरीक्षण एवं परीक्षण के दायरे में आया। योजना आयोग अग्रलिखित विसंगतियों से ग्रस्त था –

1. योजना आयोग देश में सतत् रूप से उच्च वृद्धि दर हासिल करने में असफल रहा। 1980 तक भारत में वृद्धि दर 3 प्रतिशत के लगभग रही। जिससे देश विकासशील बना रहा। 2005–07 के दौरान भारत में वृद्धि दर 9 प्रतिशत रही लेकिन यह वैश्विक स्तर पर आई तेजी की वजह से थी, क्योंकि शेष विश्व में भी इस दौरान उच्च वृद्धि दर देखी गई। 2007 के बाद अमेरिका में सब प्राइम संकट उभरा जिससे अमेरिका में मंदी आई। भारत में भी इस मन्दी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा व योजना आयोग भारत में पड़ने वाले प्रभावों को रोकने में नाकामयाब रहा।2. 2008–13 के दौरान भारत में निरन्तर मुद्रास्फीति (Inflation) बढ़ी जिससे महंगाई बढ़ती गई।

योजना आयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जाने पर भी कोई भी मंत्रालय, विभाग या राज्य आदि इससे कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं थे, अर्थात् यह किसी के प्रति प्रत्यक्षतः जवाबदेह नहीं था।

3. भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में योजना आयोग असफल रहा। इसी वजह से भारत का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित हो गया। योजना आयोग की स्थापना के 65 वर्ष बाद भी देश में औद्योगीकरण, कारखाना श्रमिक कानून आदि अनेक समस्याएं बनी हुई है।
4. देश में योजना व नीति निर्माण हेतु नए प्रकार के संगठन उभरे यथा– प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्, प्रधानमंत्री परियोजना अनुश्रवण(Monitoring) समूह आदि। योजना आयोग के साथ इनका प्रभावशाली तालमेल नहीं बैठ पाया।
5. 1950 में भारत में जबरदस्त आर्थिक पिछड़ापन था, अतः उसके निवारण हेतु योजना आयोग जैसी केन्द्रीकृत संस्था उचित थी। आज 2017–18 में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। अतः भारत को ओर आगे बढ़ाने हेतु योजना आयोग की क्षमता जवाब दे गई थी। आज के शक्तिशाली भारत को महाशक्ति बनाने हेतु **नई** नियोजन संस्था की स्थापना की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस हो रही थी।

भारतीय प्रशासन के समक्ष एक अच्छे अभिशासन (Good Governance) को स्थापित करने के मार्ग में अनेक चुनौतियाँ मौजूद है। इन चुनौतियों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, विकास में असंतुलन के कारण सामाजिक उथल–पुथल आज भारत की सामान्य स्थिति हो गई है। नक्सलवाद तथा अन्य रूढ़ीवादी प्रवृतियों ने देश के सभी भागों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। आर्थिक पिछड़ापन देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। यद्यपि देश ने आर्थिक प्रगति है तथापि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आर्थिक विकास का लाभ देश के गरीबों तक पहुँच नहीं पाया है। नीति–निर्देशक तत्वों में उल्लिखित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता हमें नहीं मिल पायी है। पर्यावरणीय प्रदूषण देश के सामने एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। बेतरतीब औद्योगिकीकरण जंगलों का कटाव तथा प्राकृतिक संसाधनों का अबौद्धिक इस्तेमाल वातावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे मानव समाज के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ है। समाज के भीतर असमानता के तत्व बढ़े हैं। सामाजिक दूरियाँ बढ़ी हैं इससे आर्थिक उन्मादता बढ़ी है। भारत में मानव संसाधन विकास का भी पर्याप्त अभाव देखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अर्थपूर्ण रोजगार के अभाव में पर्याप्त ढंग से मानव विकास संभव नहीं हो पाया है। मानव विकास प्रतिवेदनों में भारतीय मानव विकास पर गंभीर चिंता दर्ज करायी गयी। जनसंख्या दर को नियंत्रित करने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों का पर्याप्त लाभ सभी लोगों तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। चीन तथा दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों की तरह भारत की आर्थिक प्रगति निरंतर गतिशील नहीं हो पा रही है। नियोजन में राज्य, जिला एवं खण्ड स्तरों की अत्यन्त सीमित भूमिका के कारण जन सहभागिता अत्यन्त न्यून है। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर इसकी जगह नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना की गई।

नीति आयोग (NITI Aayog) – नीति आयोग जिसे **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान** (National Institute For Transforming India) भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। यह 1 जनवरी, 2015 को अस्तित्व में आया। इस आयोग का गठन उन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु किया गया जो अभी पूर्णतः फलीभूत नहीं हो पायी है यथा :

1. अभी तक गरीबी के उपशमन (कमी) का लक्ष्य था योजना आयोग ने गरीबी कम करने की दिशा में गम्भीर प्रयास किए। लेकिन भारत से गरीबी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई। स्वयं योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु विभिन्न अध्ययन दल गठित किए, किन्तु ये अध्ययन दल गरीबी की निश्चित एवं सर्वस्वीकृत परिभाषा करने में असफल रहे। लेकिन अब गरीबी के पूर्ण उन्मूलन की मांग है।
2. नियोजन में वित्तीय आवंटन को ले कर विभिन्न राज्यों में उपजे तनाव का निराकरण करना। योजना आयोग का दायित्व विभिन्न राज्यों को अनुदान के रूप में वित्त राशि उपलब्ध करवाना रहा है। इस अनुदान के वितरण को लेकर विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए है। राज्यों का मानना है कि योजना आयोग उन राज्यों को अधिक अनुदान स्वीकृत करता है, जहाँ केन्द्र–राज्य में एक समान दल वाली सरकार हो।
3. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में सरकार की भूमिका को कम किया जाए, अब सरकार केवल समर्थकारक बने, न की स्वयं प्रथम प्रदाता की भूमिका निभाए। आज विकास हेतु यह सम्पूर्ण विश्व में यह दृष्टिकोण उभरा है कि जहां भी निजी क्षेत्र (Private Sector) सही एवं प्रभावशाली ढंग से काम करे उसे करने देना चाहिए तथा जहां निजी क्षेत्र कार्य नहीं करे उस क्षेत्र में सरकार को कार्य करना चाहिए। आज सरकार से मुख्य अपेक्षा यह है कि वह उचित ढंग से कानून का पालन करवाए (Rule of Law), सामाजिक सेवाओं यथा– शिक्षा, चिकित्सा आदि में निवेश करे। कमजोर एवं पिछड़े वर्गों का संरक्षण करे तथा पर्यावरण की सुरक्षा करे।
4. उद्यमशीलता, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक मानव पूंजी को देशहित में नवीन उँचाइयों पर ले जाना।
5. प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अनिवासी भारतीय समुदाय से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना।
6. आने वाले समय में भारत की विशाल जनसंख्या से लाभ उठाना।
7. भारत के गांव लोकाचार, संस्कृति तथा जीविका के सुदृढ़ आधार बने हुए है। इन्हें विकास प्रक्रिया में पूर्णरूप से संस्थागत बनाये जाने की आवश्यकता है, जिससे हम उनके उत्साह एवं ऊर्जा का लाभ उठा सकें।

उपर्युक्त तथा ऐसी ही अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है।

नीति आयोग योजना आयोग से निम्न प्रकार भिन्न है

कारक	नीति आयोग	योजना आयोग
नियोजन	नीचे से ऊपर नियोजन(Bottom-up approach)	ऊपर से नीचे नियोजन(Top-down approach)
वित्तीय शक्तियाँ	सलाहकारी (शक्तियाँ वित्त मंत्रालय में)	वित्तीय शक्तियों का उपयोग
राज्यों की भूमिका	शासी परिषद् (Governing Council) के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका	राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य के रूप में भूमिका
नियोजन की प्रकृति	संकेतात्मक एवं अधिक गुणवत्तापूर्ण	केन्द्रीकृत एवं मात्रात्मक

उद्देश्य (Objectives) : भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के कार्यकरण हेतु अपने संकल्प पत्र में कुछ उद्धेश्यों का निर्धारण किया गया है। ये अग्रलिखित है :

क. राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों हेतु एक साझा दृष्टिकोण का विकास करना। इस हेतु राज्य की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना।

ख. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते है, इसे मानते हुए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सहयोग करेगी। सहयोगी संघवाद की स्थापना करना।

ग. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने हेतु नीति आयोग एक ढांचा विकसित करेगा।

घ. जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को सौंपे गए है उनके लिए क्षेत्रगत आर्थिक रणनीति तैयार करना।

ड. समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना।

च. लम्बी अवधि हेतु नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। इन नीतियों तथा कार्यक्रमों की निरन्तर देखरेख करना तथा इनमें मध्यावधि संशोधन करना।

छ. शैक्षणिक एवं नीति अनुसंधान संस्थाओं के मध्य परस्पर परामर्श एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

ज. राष्ट्र के विकास के विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न विभागों को एक मंच प्रदान करना।

झ. सुशासन (Good Governance) तथा सतत् एवं न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु अनुसंधान पर जोर देना।

ण. विकास तथा नियोजन हेतु आवश्यक संसाधनों की पहचान करना।

ट. कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन करना व निगरानी रखना जिससे इनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इस हेतु तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर देना।

ठ. उपर्युक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

संगठन (Organisation) :

नीति आयोग का संगठन योजना आयोग से मिलता–जुलता है। संगठन से अभिप्राय है कि आयोग में कौन–कौन से सदस्य होंगे तथा इसका गठन किस प्रकार होगा। योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है। अर्थात् भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये भारत सरकार के कार्यकारी संकल्प से सृजित संस्था है। इसकी संरचना अग्रलिखित है :

1. भारत के प्रधानमंत्री इसके **अध्यक्ष** है।

2. **शासी परिषद् (Governing Council)** :– नीति आयोग की एक गवर्निंग काउन्सिल होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के (जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री) उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे।

3. **क्षेत्रीय परिषद्** :–विशिष्ट मुद्दों तथा ऐसे आकस्मिक रूप से उभरने वाले मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो से निपटने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल हेतु बनाई जाऐंगी। भारत के प्रधानमंत्री (आयोग के अध्यक्ष) के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी तथा इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे।

4. विशेष कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ प्रकृति के व्यक्तियों को विशिष्ट आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

5. आयोग के **पूर्णकालिक संगठनात्मक** ढांचे में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

क. भारत के **प्रधानमंत्री** आयोग की अध्यक्षता करते है, तथा उनकी सहायता हेतु एक **उपाध्यक्ष** होगा जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष का पद पूर्णकालिक है तथा इसे केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया है। ये अर्थशास्त्री है।

ख. **अंशकालिक सदस्य** :– अंशकालिक सदस्य वह होते है जिन्हें कुछ समय हेतु नियुक्त किया जाता है। अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों आदि से अधिकतम दो पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर नियुक्त किये जाते है।

ग. **पदेन सदस्य** :– पदेन सदस्य वह होते है जिन्हें स्वयं के पद के आधार पर (न कि व्यक्ति) स्वतः सदस्यता प्राप्त होती

है। नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रीपरिषद् से अधिकतम चार सदस्य नामित किये जाते है। पहली बार नियुक्त किये गये पदेन सदस्यों में केन्द्र के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री तथा कृषि मंत्री शामिल है। विशेष रूप से आमंत्रित किये गये मंत्रियों में केन्द्रीय परिवहन मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री शामिल है।

घ. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO)** : भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल हेतु मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में अमिताभ कांत (मार्च 2017) सी.ई.ओ. है। आयोग का एक सचिवालय होगा जिसमें आयोग को सचिवालय प्रकृति की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

प्रथम बैठक (First Meeting) –

फरवरी, 2015 में नवनिर्मित नीति आयोग की प्रथम बैठक हुई इसमें आयोग के अध्यक्ष ने राज्यों को सभी मतभेद भुलाकर ''सहयोगी संघवाद'' के मॉडल पर काम करने की सलाह दी। प्रथम बैठक में निर्धनता उन्मूलन को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद्) की इस बैठक में मुख्यमंत्रियों की तीन उप समितियाँ बनाई गई। ये समितियां केन्द्र सरकार द्वारा पोषित 66 योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास तथ स्वच्छता को भारतीय जीवन में पूर्ण शुचिता से अंगीकार करने वाली संस्थागत प्रणाली को विकसित करने का महत्वाकांक्षी कार्य निष्पादित करेंगी। प्रत्येक राज्य अपने–अपने क्षेत्र में दो टास्क फोर्स बनाएगा। प्रथम टास्क फोर्स राज्य में पूर्ण गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करेगी। द्वितीय टास्क फोर्स द्वारा राज्य के भावी विकास, कृषि तथा संबंधित कार्यों में केन्द्र सरकार किस तरह राज्यों का सहयोग करे, इस दिशा में गम्भीरता से कार्य करेगी। टास्क फोर्स एक ऐसा कार्यबल (समूह) होता है जिसका गठन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अस्थाई रूप से किया जाता है। नीति आयोग का प्रशासनिक संगठन (सचिवालय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन काम करता है। नई दिल्ली के योजना भवन में नीति आयोग का प्रशासनिक सचिवालय कार्यरत है।

नीति आयोग की संरचना

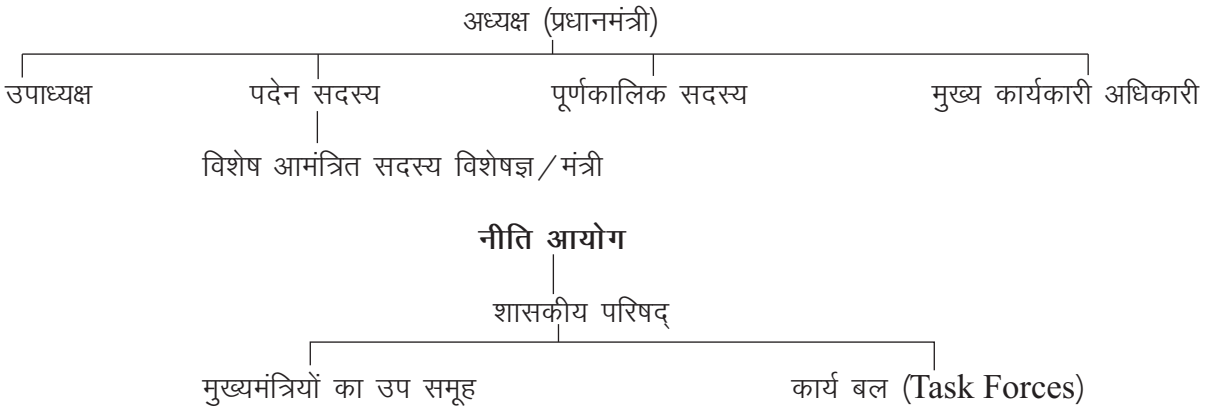

मूल्यांकन (Evaluation) –

भारत में बेहतर नियोजन हेतु योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। अभी नीति आयोग की शिशु अवस्था है तथापि इसके विरूद्ध अग्रलिखित आक्षेप लगाए जा रहे है :

1. नीति आयोग के संकल्प पत्र में आयोग के कार्यों तथा क्षेत्राधिकार का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया है। इससे नीति आयोग में योजना आयोग जैसी प्रवृत्तियाँ ग्रहण करने का अंदेशा बना हुआ है।
2. भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् से बिना विचार विमर्श किया गया है। इससे देश में सहकारी संघवाद की भावना पर प्रहार हुआ है।
3. योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी कार्यकारी संकल्प से सृजित किया गया है। इसे संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया जाता तो यह अधिक सम्मानीय एवं प्रभावशाली हो सकता था।

अभी नीति आयोग का गठन हुए कम समय हुआ है ऐसे में किसी संस्था की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता का उचित मापन सम्भव नहीं हो सकता। तथापि भारत सरकार ने नीति आयोग (NITI – National Institute for Transforming India) का सृजन नियंत्रक आयोग के रूप

में नहीं कर के थिंक टैंक (Think Tank) के रूप में किया है। अतः इसका मुख्य दायित्व देश के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के नये विचारों को प्रोत्साहन देना है। आज भारत के समक्ष विकास हेतु अनेक चुनौतियां है जिनका निराकरण केन्द्र एंव राज्य दोनों मिलकर नीति आयोग के तत्त्वावधान में कर सकते है।

महत्वपूर्ण बिन्दू

1. नियोजन में, एक देश में उपलब्ध भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों का व उनसे हो सकने वाले आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाना हैं।
2. पहली बार नियोजित विकास का विचार श्री एम. विश्वेश्वरैया से सन् 1934 में दिया था।
3. एक गैर संविधानिक संस्था के रूप में योजना आयोग की स्थापना केन्द्रीय सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा 15 मार्च, 1950 को की गई थी।
4. मूल रूप में योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था मात्र हैं, किन्तु देश के नियोजित विकास में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5. केन्द्रीय स्तर के नियोजन तंत्र की प्रमुख संस्थाएँ योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् हैं। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर इसकी जगह नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना की गई।
6. भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। भारत में अभी तक 11 पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है, तथा वर्तमान में 12 वीं योजना चल रही है।
7. बारहवीं योजना (2012–2017) – इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत का **तेज, अधिक समावे□ी एवं सतत् विकास** (Faster,More Inclusive and Sustainable Growth) करना है। यह योजना वर्तमान में जारी है इस योजना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर 8 प्रतिशत विकास दर प्राप्ति का लक्ष्य है।
8. नीति आयोग जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institute For Transforming India) भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। यह 1 जनवरी, 2015 को अस्तित्व में आया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. भारत में विकास हेतु किस पर जोर दिया गया है –
(अ) नियोजन (ब) सलाह
(स) क्रान्ति (द) सामग्री

2. निम्नलिखित में से नियोजन पर किसने बल दिया है –
(अ) सेकलर–हडसन (ब) कौटिल्य
(स) हेनरी फेयोल (द) सभी

3. नियोजन के माध्यम से एक देश में कौन–कौन से परिवर्तन आ सकते है –
(अ) आर्थिक स्थिरता (ब) असमानता में कमी
(स) क्षेत्रीय विकास (द) सभी

4. भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी –
(अ) 15 मार्च, 1949 (ब) 15 मार्च, 1950
(स) 15 मार्च, 1951 (द) 15 मार्च, 1952

5. भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई –
(अ) 1 जनवरी, 2010 (ब) 1 जनवरी, 2012
(स) 1 जनवरी, 2015 (द) 1 जनवरी, 2016

6. नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?
(अ) मुख्यमंत्री (ब) राज्यपाल
(स) प्रधानमंत्री (द) राष्ट्रपति

7. नियोजन का अर्थ है :
(अ) पूर्व दृष्टि (ब) दूर दृष्टि
(स) पूर्व तैयारी (द) उपर्युक्त सभी

8. ''प्लाण्ड इकॉनामी फॉर इण्डिया'' पुस्तक के लेखक हैं :
(अ) एम. विश्वेश्वरैया (ब) जवाहरलाल नेहरू
(स) श्रीमति इंदिरा गांधी (द) के.सी.नियोगी

9. योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं :
(अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
(स) गृहमंत्री (द) राज्यपाल

10. योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा हुई ?
(अ) राष्ट्रपति (ब) संसद
(स) मंत्रिमण्डल (द) राज्यसभा

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. नियोजन से आप क्या समझते है ?
2. भारत में नियोजन का नाम सर्वप्रथम कब सुनने में आया?
3. योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था ?
4. नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताईये ।

5. योजना आयोग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गयी थी?
6. योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या थे ?
7. सामान्यतः योजना अयोग का अध्यक्ष कौन होता था ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. वर्तमान में नियोजन का क्या महत्व है ?
2. भारत में नियोजन कब से आरम्भ हुआ ?
3. योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन क्यों किया गया ?
4. नीति आयोग पर कौनसी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का दायित्व है ?
5. योजना आयोग के प्रमुख तीन कार्य बताईये।
6. योजना आयोग की कोई तीन उपलब्धियाँ बताईये।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. नियोजन का अर्थ समझाते हुए भारत में इसकी आवश्यकता का विवेचन कीजिए।
2. नीति आयोग से जनता की आकांक्षाओं एवं इसके उद्धेश्यों पर प्रकाश डालिए।
3. नीति आयोग की संरचना पर लेख लिखिए।
4. योजना आयोग के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिये।

उत्तरमाला :

1. (अ)	2. (द)	3. (द)	4 (ब)
5. (स)	6. (स)	7. (द)	8. (अ)
9. (अ)	10. (स)		